करायी है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र, गुजरात को सहायता की है उसी तरह उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देकर, उसकी सहायता की जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं जो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2003 में एम्स की तरह की 6 संस्थाएं देश के दूसरे हिस्सों में बनाने की योजना बनी थी। ये 6 संस्थाएं बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में बनने वाली थीं। उसका काम शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद काम रुक गया। मैंने यह विषय 21 दिसम्बर 2004 को एक कॉलिंग अटैंशन के माध्यम से रखा था।

उस दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि वह भी इससे सहमत हैं कि इसे जल्दी बनना चाहिए लेकिन प्रक्रिया और एप्रूवल्स में कुछ समय लग रहा है। दिसंबर में ही उन्होंने कह दिया था कि एक्पेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने इसे क्लियर कर दिया है अब सिर्फ सरकार का एप्रूवल रहता है। इस प्रकार की संस्था उत्तरांचल के ऋषिकेश में खुलने वाली थी, बनने वाली थी। वहां पर पहले साल में एक करोड़ रुपया दिया गया था और चारदीवारी पूरी की गई थी, मगर उसके बाद काम रुक गया। अभी, 17 अगस्त को प्रश्न संख्या 3398 के माध्यम से मैंने फिर सरकार से पूछा था कि स्थिति क्या है? सरकार का जवाब था कि अभी भी यह प्रोग्रेस में है। मैं लीडर ऑफ दि हाऊस, श्री प्रणव मुखर्जी से निवेदन करता हूं कि सरकार से, कैबिनेट से, इन संस्थाओं का जो एप्रूवल लेना है, कृपया उसे जल्दी ले लीजिए क्योंकि पूरे देश में छः स्थानों पर ये संस्थाएं बननी हैं, यह बहुत कठिन और बड़ी समस्या है। मेरा आपसे आग्रह है कि कैबिनेट से जो स्वीकृति मिलनी है, इसे जल्दी करा दीजिए। यू.पी.ए. सरकार को डेढ़ साल हो गया है, और यह स्वीकृति लम्बित पड़ी है । इसे जल्दी करा दीजिए।